नईदुनिया

खास-खबरें

एलएपीएल ऑटोमोटिव की स्टॉक मार्केट में मजबूत शुरुआत

नईदुनिया ब्यूरो, नईदिल्ली: ऑटो कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनी एलएपीएल ऑटोमोटिव के शेयरों ने आज स्टॉक मार्केट में मजबूत शुरुआत कर अपने आईपीओ निवेशकों को खुश कर दिया। आईपीओ के तहत कंपनी के शेयर 94 रुपये के भाव पर जारी किए गए थे। आज बीएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर इसकी लिस्टिंग 43.62 प्रतिशत प्रीमियम के साथ 135 रुपये के स्तर पर हुई। लिस्टिंग के बाद लिवाली के सपोर्ट से ये शेयर उछल कर 139 रुपये के स्तर पर आ गया। हालांकि बाद में मुनाफा वसूली शुरू हो जाने की वजह से कंपनी के शेयर 128.25 रुपये के स्तर तक गोता लगा कर बंद हुए। दिन के दूसरे सत्र में जमकर हुई मुनाफा वसूली के बावजूद पहले दिन के कारोबार में कंपनी के आईपीओ निवेशकों को प्रति शेयर 34.25 रुपये यानी 36.44 प्रतिशत का फायदा हो गया। इस कंपनी का 32.40 करोड़ रुपये का आईपीओ 06 से 10 अगस्त के बीच सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था। इस आईपीओ को निवेशकों की ओर से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था, जिसके कारण ये ओवरऑल 344.31 गुना सब्सक्राइब हुआ था। इनमें क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (क्यूआईबी) के लिए रिजर्व पोर्शन 200.23 गुना सब्सक्राइब हुआ था।

दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में मिलेगा संपत्ति का पक्का मालिकाना हक

नईदुनिया ब्यूरो, नईदिल्ली: दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को संपत्ति का पक्का मालिकाना हक देने की प्रक्रिया को दो प्रमुख चरणों में समझा जा सकता है। इसके तहत पहले संपत्ति से जुड़े दस्तावेज और जानकारी तैयार करनी होगी। इसके बाद संबंधित प्रक्रिया पूरी कर स्वामित्व का अधिकार प्राप्त किया जा सकेगा। अनधिकृत कॉलोनियों में संपत्ति के मालिकाना हक से जुड़ी व्यवस्था के तहत निवासियों को अपनी संपत्ति का विवरण उपलब्ध कराना होगा। इसके लिए संबंधित दस्तावेजों की जरूरत होगी। इनमें संपत्ति की खरीद-बिक्री से जुड़े कागजात और अन्य उपलब्ध प्रमाण शामिल हो सकते हैं। पहले चरण में संपत्ति से संबंधित दस्तावेजों और जानकारी को तैयार करना जरूरी होगा। इसके बाद आवेदन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। आवेदन में संपत्ति का सही विवरण और जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे। दस्तावेजों की जांच के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। दूसरे चरण में आवेदन और दस्तावेजों के सत्यापन के बाद संपत्ति के मालिकाना हक से संबंधित अधिकार प्रदान करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इस पूरी व्यवस्था का उद्देश्य अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को उनकी संपत्ति पर कानूनी अधिकार उपलब्ध कराना है। दिल्ली के निवासियों के लिए इस प्रक्रिया में सही दस्तावेज तैयार रखना महत्वपूर्ण है। संपत्ति से संबंधित जानकारी में किसी तरह की गलती या दस्तावेजों की कमी होने पर आवेदन की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। इसलिए आवेदन से पहले उपलब्ध दस्तावेजों और संपत्ति के विवरण की जांच करना जरूरी होगा। अनधिकृत कॉलोनियों में संपत्ति के मालिकाना हक से जुड़ी यह व्यवस्था लंबे समय से संपत्ति संबंधी अधिकारों की समस्या का सामना कर रहे लोगों के लिए महत्वपूर्ण है।

सोना 972 रुपये सस्ता, चांदी के भाव में 3,414 रुपये की गिरावट

24 कैरेट सोना 1.52 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम, चांदी 2.34 लाख रुपये प्रति किलो पर पहुंची

नईदुनिया ब्यूरो, नईदिल्ली: सोने और चांदी की कीमतों में गुरुवार, 13 अगस्त को गिरावट दर्ज की गई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) के मुताबिक, 24 कैरेट सोने की कीमत 972 रुपये घटकर 1.52 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गई। वहीं, एक किलो चांदी का भाव 3,414 रुपये की गिरावट के साथ 2.34 लाख रुपये रह गया। इस साल सोने और चांदी की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। वर्ष 2026 में अब तक सोने की कीमत करीब 19 हजार रुपये बढ़ चुकी है। 31 दिसंबर 2025 को 10 ग्राम सोने की कीमत 1.33 लाख रुपये से अधिक थी, जो अब बढ़कर 1.52 लाख रुपये हो गई है।

चांदी की कीमत में भी इस साल अब तक करीब चार हजार रुपये की बढ़ोतरी हुई है। 31 दिसंबर 2025 को चांदी 2.30 लाख रुपये प्रति किलो थी, जो अब 2.34 लाख रुपये प्रति किलो पर है। इस दौरान 29 जनवरी को सोने ने 1.76 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी ने 3.86 लाख रुपये प्रति किलो का ऑलटाइम हाई बनाया था।

सोना खरीदते समय ग्राहकों को ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स (बीआईएस) का हॉलमार्क लगा सर्टिफाइड गोल्ड खरीदने की सलाह दी जाती है। हॉलमार्क से सोने की शुद्धता और कैरेट की जानकारी मिलती है। इसके साथ ही खरीदारी के दिन सोने की कीमत और वजन को अलग-अलग सोर्स से क्रॉस चेक करना चाहिए। 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट सोने की कीमत अलग-अलग होती है। असली चांदी की पहचान के लिए मैग्नेट, आइस, स्मेल और क्लॉथ टेस्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है। असली चांदी चुंबक से नहीं चिपकती और उसमें गंध नहीं होती। सफेद कपड़े से रगड़ने पर काला निशान आना भी असली चांदी की पहचान माना जाता है।

1988 से टाटा ग्रुप से जुड़े हैं टाटा स्टील के मैनेजिंग डायरेक्टर, फरवरी 2027 तक पूरा होगा चंद्रशेखरन का कार्यकाल

टाटा संस के नए चेयरमैन की रेस में टीवी नरेंद्रन सबसे आगे

नईदुनिया ब्यूरो, नईदिल्ली: टाटा संस के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन के इस्तीफे के बाद नए चेयरमैन की तलाश शुरू हो गई है। सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट ने 13 अगस्त को प्रस्ताव पारित कर पांच सदस्यीय सिलेक्शन कमेटी गठित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस पद के लिए टाटा स्टील के मैनेजिंग डायरेक्टर टीवी नरेंद्रन का नाम सबसे आगे माना जा रहा है। नरेंद्रन 1988 से टाटा ग्रुप से जुड़े हैं और उनका पूरा करियर टाटा स्टील में रहा है।

चंद्रशेखरन के इस्तीफे के बावजूद वे फरवरी 2027 तक टाटा संस के चेयरमैन पद पर बने रहेंगे। इससे कंपनी के पास नए प्रमुख के चयन और जिम्मेदारियों के सुचारू हस्तांतरण के लिए करीब छह महीने का समय है। टाटा संस के नियमों के अनुसार चेयरमैन के चयन के लिए पांच सदस्यीय कमेटी बनाई जाती है। इसमें सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और सर रतन टाटा ट्रस्ट से तीन सदस्य, टाटा संस बोर्ड की ओर से एक सदस्य और एक स्वतंत्र सदस्य शामिल होता है। कमेटी नामों की जांच और साक्षात्कार के बाद टाटा संस बोर्ड को अंतिम नाम की सिफारिश करती है।

नरेंद्रन के नाम की चर्चा की प्रमुख वजहों में टाटा स्टील में उनका अनुभव और कठिन परिस्थितियों में प्रदर्शन शामिल है। उनके कार्यकाल में कंपनी ने कर्ज कम करने, कैश फ्लो सुधारने और घरेलू कारोबार मजबूत करने पर काम किया। उन्होंने यूके और नीदरलैंड्स में पुनर्गठन से जुड़े कठिन फैसले भी संभाले। करीब चार दशक से टाटा ग्रुप से जुड़े होने के कारण उन्हें समूह की कार्यशैली और मूल्यों की गहरी समझ है। बड़े परिचालन, श्रम मामलों, नियमन और लंबे निवेश चक्र का अनुभव भी उनके पक्ष में माना जा रहा है।

नरेंद्रन अपनी दौड़ने की आदत के लिए भी जाने जाते हैं। वे सुबह करीब नौ किलोमीटर दौड़ते हैं। 40 वर्ष की उम्र में उन्होंने ड्रम बजाना सीखना शुरू किया और करीब तीन साल तक इसकी शिक्षा ली। उनके नाना ई. इक्कंडा वॉरियर तत्कालीन कोचीन राज्य के पहले प्रधानमंत्री और स्वतंत्रता सेनानी थे।

चेयरमैन चयन की प्रक्रिया में कानूनी अड़चन भी सामने आई है। महाराष्ट्र चैरिटी कमिश्नर के निर्देश के कारण सर रतन टाटा ट्रस्ट फिलहाल ट्रस्टियों की बैठक नहीं कर पा रहा है। इससे कमेटी के लिए ट्रस्ट की ओर से तीन सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।

2016 में साइरस मिस्त्री को हटाए जाने के बाद रतन टाटा ने अंतरिम चेयरमैन की जिम्मेदारी संभाली थी। हालांकि, नोएल टाटा इस बार अंतरिम चेयरमैन नहीं बन सकते। 2022 में टाटा संस के नियमों में संशोधन के बाद टाटा ट्रस्ट्स का चेयरमैन एक साथ टाटा संस का चेयरमैन नहीं बन सकता। नोएल टाटा नवंबर में 70 वर्ष के होंगे, लेकिन ट्रस्ट के नामित सदस्य होने के कारण वे टाटा संस के बोर्ड में बने रह सकते हैं। टाटा संस टाटा ग्रुप की मुख्य होल्डिंग कंपनी है, जबकि टाटा ट्रस्ट्स के पास टाटा संस की 66 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स का मुनाफा 80% घटा

नईदुनिया ब्यूरो, मुंबई: टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स का अप्रैल-जून तिमाही में मुनाफा 80% से अधिक घटकर 775 करोड़ रुपये रह गया। पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में कंपनी को 3,924 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था। मुनाफे में गिरावट का मुख्य कारण स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति में रुकावट, एक प्रमुख कंपोनेंट सप्लायर के यहां आग, मिडिल ईस्ट में संघर्ष और जगुआर के पुराने मॉडलों का उत्पादन बंद होना रहा।

कंपनी का ऑपरेशनल रेवेन्यू सालाना आधार पर 9% बढ़कर 95,799 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले साल 87,677 करोड़ रुपये था। कंपनी का ईबीआईटीडीए मार्जिन 130 बेसिस पॉइंट घटकर 7.4% रह गया। तिमाही में 32 करोड़ रुपये का एक्सेप्शनल लॉस भी दर्ज किया गया। ईपीएस घटकर 2.10 रुपये प्रति शेयर रह गया, जबकि पिछले साल यह 6.84 रुपये था।

जगुआर लैंड रोवर का प्रदर्शन भी कमजोर रहा। जेएलआर की होलसेल बिक्री 9% घटी। सप्लायर के यहां आग, मिडिल ईस्ट संघर्ष और नए मॉडल की लॉन्चिंग से पहले पुराने जगुआर मॉडलों का उत्पादन बंद होने से बिक्री प्रभावित हुई। जेएसआर का रेवेन्यू करीब 9% घटकर 6 बिलियन पाउंड रहा।

टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के एमडी और सीईओ शैलेश चंद्रा ने कहा कि नए मॉडलों को बेहतर प्रतिक्रिया मिलने से बिक्री 46% बढ़ी है। सप्लाई की दिक्कतों से सिएरा का वॉल्यूम प्रभावित हुआ, लेकिन सियारा ईवी को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। कंपनी को मजबूत ऑर्डर बुक, नए प्रोडक्ट्स की पाइपलाइन और मार्जिन सुधार के उपायों से आने वाली तिमाहियों में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है।

सीएनजी में सीबीजी की ब्लेंडिंग शुरू होने के संकेत

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (सीएनजी) में कंप्रेस्ड बायो गैस (सीबीजी) की ब्लेंडिंग को लेकर भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) की ओर से संकेत मिला है। कंपनी के आधिकारिक वीडियो में सीबीजी को सीएनजी के साथ मिलाकर पेट्रोल पंप तक पहुंचाने और इसे सामान्य सीएनजी की तरह वाहनों में इस्तेमाल करने की जानकारी दी गई है। सीबीजी खाने के कचरे, फसलों के अवशेष और पशुओं के गोबर जैसे जैविक पदार्थों से तैयार की जाती है। वहीं, सीएनजी एक जीवाश्म ईंधन है। सीबीजी को सीएनजी में मिलाने से वाहनों के ईंधन को अधिक पर्यावरण अनुकूल बनाने में मदद मिल सकती है। इसके लिए मौजूदा सीएनजी वाहनों में किसी बड़े बदलाव की जरूरत नहीं होगी।

केंद्र सरकार ने सीबीजी को बढ़ावा देने के लिए नेशनल सर्कुलर बायो-एनर्जी स्कीम-गोवर्धन को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत सीबीजी ब्लेंडिंग को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है।

1 रुपये में 1 किलोमीटर चलेगी नई मारुति सुजुकी

पेट्रोल 316.15 और उच्च गति डीजल 354.35 रुपये प्रति लीटर, अब प्रतिदिन तय होंगी कीमतें

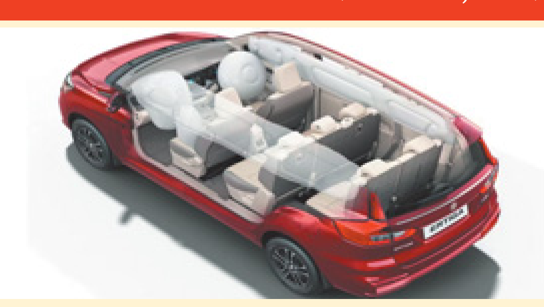

नईदुनिया ब्यूरो, नईदिल्ली: मारुति सुजुकी एक नई इलेक्ट्रिक एमपीवी लाने की तैयारी कर रही है। यह कार कंपनी की अर्टिगा के सेगमेंट में होगी और इसमें 7 लोगों के बैठने की क्षमता मिलने की उम्मीद है। नई कार को ज्यादा स्पेस और कम चलने की लागत को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है।

कंपनी की आगामी इलेक्ट्रिक एमपीवी की सबसे बड़ी खासियत इसकी कम रनिंग कॉस्ट बताई जा रही है। दावा है कि यह कार करीब 1 रुपये में 1 किलोमीटर चल सकेगी। इससे रोजाना ज्यादा दूरी तय करने वाले ग्राहकों के लिए इलेक्ट्रिक एमपीवी का खर्च पेट्रोल या डीजल कारों की तुलना में कम हो सकता है।

नई मारुति सुजुकी इलेक्ट्रिक एमपीवी को परिवारों की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। इसमें 7 लोगों के बैठने की जगह होगी। एमपीवी सेगमेंट में ज्यादा सीटिंग क्षमता के साथ बेहतर स्पेस मिलने की वजह से यह कार बड़े परिवारों के लिए उपयोगी हो सकती है।

नई इलेक्ट्रिक कार के पावरट्रेन, बैटरी क्षमता और ड्राइविंग रेंज से जुड़ी पूरी जानकारी कंपनी की ओर से सामने नहीं आई है। हालांकि, इसे इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में कंपनी की महत्वपूर्ण पेशकश माना जा रहा है। कम रनिंग कॉस्ट के साथ 7 सीटर लेआउट इसे मौजूदा एमपीवी ग्राहकों के लिए आकर्षक विकल्प बना सकता है।

मारुति सुजुकी की यह आगामी इलेक्ट्रिक एमपीवी अर्टिगा सेगमेंट में कंपनी की मौजूदगी को मजबूत कर सकती है। इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती मांग के बीच कंपनी का फोकस ऐसे मॉडल पर है, जो परिवारों को ज्यादा सीटिंग क्षमता के साथ किफायती रनिंग कॉस्ट उपलब्ध करा सके। कार की कीमत, लॉन्च तारीख, बैटरी और रेंज से जुड़ी जानकारी कंपनी की आधिकारिक घोषणा के बाद स्पष्ट होगी।

मुथूट फिनकॉर्प लाएगी 3 हजार करोड़ रुपये का आईपीओ

सेबी के पास डीआरएचपी दाखिल पूरा इश्यू फ्रेश शेयरों का होगा

नईदुनिया ब्यूरो, मुंबई:

मुथूट पप्पाचन ग्रुप की कंपनी मुथूट फिनकॉर्प 3 हजार करोड़ रुपये का आईपीओ लाने की तैयारी कर रही है। कंपनी ने इसके लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के पास ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (डीआरएचपी) दाखिल किया है। आईपीओ से जुटाई गई राशि का इस्तेमाल भविष्य की पूंजी जरूरतों, आगे कर्ज देने और कारोबार के विस्तार में किया जाएगा।

कंपनी की ओर से बुधवार को दाखिल किए गए ड्राफ्ट पेपर्स के अनुसार, आईपीओ पूरी तरह फ्रेश इश्यू होगा। यानी कंपनी नए शेयर जारी करके 3 हजार करोड़ रुपये जुटाएगी। इसमें ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) शामिल नहीं है। इसका मतलब है कि मौजूदा निवेशक अपने शेयर बेचकर इस आईपीओ से पैसा नहीं जुटाएंगे।

मुथूट फिनकॉर्प मुथूट पप्पाचन ग्रुप का हिस्सा है और इसकी शुरुआत 1887 में हुई थी। कंपनी मुख्य रूप से गोल्ड लोन कारोबार में है और पिछले दो दशकों से ज्यादा समय से इस क्षेत्र में काम कर रही है। गोल्ड लोन के अलावा कंपनी बिजनेस लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, सप्लाई चेन फाइनेंसिंग, डिजिटल लोन, माइक्रोफाइनेंस और हाउसिंग लोन भी उपलब्ध कराती है।

कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन में भी सुधार हुआ है। वित्त वर्ष 2026 में कंसोलिडेटेड प्रॉफिट तीन गुना बढ़कर 1,848 करोड़ रुपये हो गया, जबकि वित्त वर्ष 2025 में यह 607.90 करोड़ रुपये था। वहीं, ऑपरेशंस से मिलने वाला कंसोलिडेटेड रेवेन्यू बढ़कर 11,203.81 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले वित्त वर्ष में 8,497.69 करोड़ रुपये था।

फ्रेश इश्यू में कंपनी नए शेयर जारी करती है और इससे मिलने वाली पूरी राशि कंपनी के पास जाती है। इसका इस्तेमाल कर्ज चुकाने या कारोबार के विस्तार में किया जा सकता है। वहीं, ओएफएस में पुराने प्रमोटर्स या निवेशक अपने शेयर बेचते हैं और इससे मिलने वाली राशि सीधे शेयर बेचने वाले निवेशकों को मिलती है।

फर्जी लोन ऐप्स से रहें सावधान फोन में मौजूद ऐप की करें जांच

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: फर्जी लोन ऐप्स के जरिए साइबर ठगी के बढ़ते मामलों के बीच गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाली एजेंसी इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (आई4सी) ने लोगों को सतर्क किया है। एजेंसी के साइबर दोस्त प्लेटफॉर्म ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए यूजर्स को फर्जी लोन ऐप्स से सावधान रहने की सलाह दी है। साइबर अपराधी लोगों को तुरंत लोन देने का झांसा देकर मोबाइल फोन में संदिग्ध ऐप्स डाउनलोड करवा सकते हैं। ऐसे ऐप्स के जरिए यूजर्स की निजी जानकारी, बैंकिंग डिटेल्स और अन्य संवेदनशील डेटा तक पहुंच हासिल करने की कोशिश की जा सकती है। कई मामलों में ऐप डाउनलोड करने के बाद यूजर्स से अलग-अलग तरह की फीस या भुगतान की मांग भी की जा सकती है।

गूगल पिक्सल 11 सीरीज लॉन्च कीमत 89,999 रुपये से शुरू

नईदुनिया ब्यूरो, नईदिल्ली: गूगल ने अपने मेड बाय गूगल इवेंट में पिक्सल 11 स्मार्टफोन सीरीज लॉन्च की है। सीरीज में पिक्सल 11, पिक्सल 11 प्रो, पिक्सल 11 प्रो एक्सएल और पिक्सल 11 प्रो फोल्ड शामिल हैं। कंपनी ने इसके साथ पिक्सल स्मार्टवॉच और स्मार्ट टैग भी पेश किए हैं। स्मार्टफोन सीरीज की शुरुआती कीमत 89,999 रुपये है। पिक्सल 11 सीरीज के फोन बिना इंटरनेट के भी एआई फीचर और वॉयस कॉल ट्रांसलेशन प्रोसेस कर सकते हैं। इन फीचर्स के लिए क्लाउड या इंटरनेट सर्वर की जरूरत नहीं होगी। डेटा फोन के अंदर ही प्रोसेस होगा, जिससे प्राइवेसी बनाए रखने में मदद मिलेगी। गूगल पिक्सल 11 की खरीद पर 7,000 रुपये का इंस्टैंट कैशबैक और 9,000 रुपये का एक्सचेंज ऑफर दिया जा रहा है। इस तरह ग्राहक 16,000 रुपये तक बचा सकते हैं। वहीं, पिक्सल 11 प्रो, पिक्सल 11 प्रो एक्सएल और पिक्सल 11 प्रो फोल्ड पर 10,000 रुपये का कैशबैक और 9,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस मिलेगा। इन मॉडलों पर कुल 19,000 रुपये तक की बचत हो सकती है। ऑफर 31 अगस्त 2026 तक लागू है। गूगल फोन पर 7 साल यानी 2033 तक ओएस अपडेट, सिक्योरिटी अपडेट, फीचर ड्रॉप और एआई इनोवेशन का सपोर्ट देगा। सीरीज में जेमिनी इंटेलिजेंस, जेमिनी नैनो, जेमिनी लाइव, जेमिनी एप्स, लाइव ट्रांसलेशन, हाइलाइट और कॉल असिस्ट जैसे फीचर मिलेंगे। फोन में ऑन-डिवाइस जेनरेटिव एआई दिया गया है, जो बिना इंटरनेट के एआई टास्क प्रोसेस कर सकता है। मैजिक कैप्चर के जरिए फोटो और वीडियो एक साथ रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। ऑफलाइन वॉयस ट्रांसलेशन लाइव कॉल के दौरान दोनों तरफ की भाषा को दूसरी भाषा में बदल सकता है। स्मार्ट एआई एडिटिंग से फोटो में अनचाही चीजें हटाने, बैकग्राउंड बदलने और धुंधली फोटो को बेहतर करने की सुविधा मिलेगी।

बिना इंटरनेट एआई फीचर और ऑफलाइन कॉल ट्रांसलेशन, 7 साल तक मिलेगा अपडेट सपोर्ट

आदेश | एक दशक पुराने विवाद का तार्किक समाधान जरूरी, ईडी से संपत्तियों और जांच की स्थिति का मांगा ब्यौरा

माल्या-बैंक विवाद खत्म करने की जरूरत: बॉम्बे हाईकोर्ट

नईदुनिया ब्यूरो, मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने भगोड़े कारोबारी विजय माल्या और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की अगुआई वाले बैंकों के बीच चल रहे कॉमर्शियल विवाद को खत्म करने की जरूरत बताई है। कोर्ट ने कहा कि करीब एक दशक से चल रहे इस विवाद को अब लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचना चाहिए। कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से मामले की मौजूदा जांच स्थिति और अटैच की गई संपत्तियों का ब्योरा भी मांगा है। जस्टिस मिलिंद जाधव की सिंगल जज बेंच माल्या की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। माल्या ने संपत्तियों को बैंकों को सौंपने से जुड़े आदेश को चुनौती दी है। कोर्ट ने कहा कि अगर दोनों पक्ष विवाद को खत्म कर आगे नहीं बढ़ते हैं तो इसका देश की अर्थव्यवस्था पर सीधा और नकारात्मक असर पड़ सकता है। कोर्ट ने कहा कि कॉमर्शियल विवादों का समाधान अक्सर विवाद के भीतर ही मौजूद होता है और पक्षों को प्रैक्टिकल सॉल्यूशन की ओर बढ़ना चाहिए। माल्या ने 2020 में विशेष प्रीवेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। इस आदेश में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अगुआई वाले बैंकों के कंसोर्टियम को श्रष्ठ द्वारा अटैच की गई माल्या की संपत्तियों का उपयोग करने की अनुमति दी गई थी। माल्या पर बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस के लिए कई बैंकों से करीब 9,000 करोड़ रुपये का लोन लेकर डिफॉल्ट करने का आरोप है। विजय माल्या मार्च 2016 में भारत छोड़कर यूके चला गया था। वर्ष 2019 में उसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम के तहत भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया। इस कानून के तहत उसकी संपत्तियों को अटैच करने और उनसे बैंकों का बकाया वसूलने की कार्रवाई की जा सकती है। भारत सरकार लगातार उसके प्रत्यर्पण की कोशिश कर रही है। इससे पहले फरवरी में चीफ जस्टिस चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अनखड की बेंच ने माल्या की दो याचिकाओं पर सुनवाई की थी। कोर्ट ने कहा था कि जब तक माल्या भारत लौटकर उसके क्षेत्राधिकार में सरेंडर नहीं करता, तब तक उसकी याचिका पर विचार नहीं किया जाएगा। 18 फरवरी की सुनवाई में माल्या ने कहा था कि इंग्लैंड की अदालतों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण वह फिलहाल भारत लौटने की तारीख नहीं बता सकता। माल्या की ओर से सीनियर एडवोकेट अमित देसाई ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा था कि याचिकाकर्ता की गैर-मौजूदगी में भी संवैधानिक अदालतें रिट याचिकाओं पर फैसला कर सकती हैं।